(b) if so, what are the likely effect of these decisions on India's defence?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI A. A. RAHIM): (a) U.S. Ambassadors in South Asia held their customary meeting in Dhaka in February 1984. The meeting was also atttended by State Department officials from Washington. Government of India have no information regarding any specific decisions taken at the meeting. Government are aware of reports regarding U. S. interest seeking facilities in Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka. However, the U.S. Government have denied such reports.

(b) Government remain vigilant about any developments which might affect the country's security.

Discourteous behaviour shown to the President Entourage at Los Angles

1153. SHRI INDRADEEP SINHA:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the President entourage was not shown due courtesy by U.S. officials at Los Angeles on their arrival from the visit to the Letin American countries;

(b) if so, whether the matter was discussed with the U.S. Vice-President when he visited India recently; and

(c) if so, what was his reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI A. A. RAHIM): (a) to (c) During the Presidential party's halt in Los Angeles airport, the treatment accorded by U.S. Customs to some members of the President's entourage was found to be less than courteous. The matter was brought to the attention of the U.S. Government through diplomatic channels. The U.S. Government, through their Embassy in Delhi, expressed regret over the incident. The necessity of taking up this matter during the visit to India of the U.S. Vice President did not arise.

कोलहन राज्य की स्थापना के लिए बिहार में आन्दोलन

1154. **श्री कैलाशपति मिश्र :**
श्री अश्विनी कुमार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जुलाई, 1984 के स्टेट्समैन में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि बिहार के चाइबासा क्षेत्र में कालहन नाम के स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य की स्थापना के लिये आंदोलन शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार के पृथकतावादी आंदोलन पर नियन्त्रण रखने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सरकार को समाचार की जानकारी है ।

(ख) चाइबासा कस्बे के अतिरिक्त चाइबासा सदर और सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर उपमंडल के इलाकों को कोल्हन क्षेत्र कहा जाता है । कोल्हन क्षेत्र में कोल्हन रक्षा संघ कहा जाने वाला एक संगठन अक्तूबर, 1978 में बनाया गया था । संघ कोल्हन आदिवासी पट्टी की स्वतन्त्रता

की मांग करता रहा है जिसमें सिंहभूम जिले के लगभग 1400 गांव शामिल हैं। संघ का यह कहना है कि यह क्षेत्र, जो "विल्किंसंस नियमों" द्वारा शासित होता था जिसके अन्तर्गत सभी कार्यकारी, न्यायिक, राजस्व तथा पुलिस शक्तियां मानकियों और मुंडाओं जैसे आदिवासीय गांव के अहलकारों में निहित है, उनको स्वायत्तता प्रदान करता है।

श्री नारायण जोनको को संघ का अध्यक्ष, श्री कृष्ण चन्द्र हेमब्राम को महामंत्री और श्री क्राइस्ट आनन्द टोपनों का कानूनी सलाहकार बताया जाता है।

1980-81 में कोल्हन रक्षा संघ ने सिंहभूम जिले में कीमती वनों को काटने के लिये एक आंदोलन शुरू किया था। वे उन आदिवासियों पर हमले करते रहे हैं और उनकी हत्या भी करते रहे हैं जो अलग कोल्हन राज्य के लिये उनकी मांग का समर्थन नहीं करते। बताया जाता है कि पिछले 8 महीनों के दौरान संघ ने 17 व्यक्तियों की हत्या की है और 49 व्यक्तियों का अपहरण किया है।

सूचनाओं के अनुसार श्री नारायण जोनको और श्री क्राइस्ट आनन्द टोपनों ने सितम्बर, 1981 में लन्दन और जेनेवा का दौरा किया था। इन दौरों के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को "कोल्हन सरकार" के लिये स्वतन्त्र दर्जे और संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता की मांग करते हुये ज्ञापन दिये थे। संघ ने नवम्बर, 1983 में नई दिल्ली में हुये राष्ट्र मण्डल देशों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के अध्यक्ष को भी कोल्हन सरकार का अनुसमर्थन करने का अनुरोध करते हुये एक ज्ञापन दिया था।

(ग) सरकार संघ की गतिविधियों के बारे में सतर्क है। बिहार पुलिस द्वारा भा०द०स० की धारा 124-क और 120 ख के अन्तर्गत राजविद्रोह के अपराध के लिये संघ के 16 सदस्यों के विरुद्ध अभियोजन शुरू किया गया है। उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था प्रवर्तन तन्त्र को सुदृढ़ कर दिया गया है। क्षेत्र में विकास गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं, विशेष रूप से पेय जल, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा और उचित दर दुकानों की सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है। बिहार सरकार के कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता 1983-84 में 15.66 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1984-85 में 18.23 करोड़ रुपये कर दी गई है। बिहार सरकार आदिवासी व्यक्तियों द्वारा स्थानीय प्रशासन के विकास तथा नियामक दोनों प्रकार के कार्य क्षेत्रों में अधिक भाग लेने के लिये कदम उठा रही है। अवैध रूप से वनों को कटाई को रोकने के लिये संवेदनशील क्षेत्रों में मजिस्ट्रेटों सहित सशस्त्र टुकड़ियां तैनात की गई हैं। स्थानीय प्रशासन को लोगों को शिकायतों को जांच करने और उनको दूर करने के लिये तुरन्त निवारक कदम उठाने के अनुदेश दिये गये हैं।

Communal Riots at Kherwadi, Bombay

1155. DR. SHANTI G. PATEL:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the recent communal riots at Kherwadi, near the Western Railway track, Khar, Bombay resulted in the death of several persons including some police personnel;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) where Government received any report to the effect that infighting between officials over the action which was to be taken in the matter aggravated the situation; and